सतीश कुमार जयंत लाल दबगर

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 230/2013)

10 मार्च, 2015

[न्यायाधिपति दीपक मिश्रा और न्यायाधिपति ए. के. सिकरी]

दंड संहिता, 1860- धारा 363, 366, 376 - 16 साल से कम उम्र की लड़की का अपहरण, उसे शादी के लिए प्रेरित करना और बलात्कार करना - आरोपी को धारा 363, 366, 376 के तहत दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई - उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, हालांकि कठोर सजा कम कर दी धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सात साल की कैद से लेकर साढ़े चार साल के कठोर कारावास तक - सजा कम करने की याचिका - आरोपी का मामला कि दोनों पक्षों के बीच हर कार्य सहमति से हुआ था - अपील पर, माना गया: तथ्यों पर, धारा 375 का खंड छठा संभोग के लिए उसकी सहमति को महत्वहीन बनाकर आकर्षित किया - नाबालिग तर्कसंगत रूप से सोचने और कोई सहमति देने में असमर्थ है - नाबालिग की सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है - किसी द्वारा दी गई तथाकथित सहमति का लाभ न उठाने का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति पर डाला जाता है 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की - यौन क्रिया में अन्य भागीदार को बलात्कार का अपराध करने वाले अपराधी के रूप में माना जाता है - 16 वर्ष से कम उम्र के अभियोजक की तथाकथित सहमति को शमन करने वाली परिस्थिति के रूप में नहीं माना जा सकता है - यदि नाबालिग की सहमति को शमन करने वाली परिस्थिति के रूप में माना जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे - इस प्रकार, आरोपी सजा में और कटौती का हकदार नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया :

1.1 उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई सजा को सही ठहराया, इससे विचलित होने का कोई कारण नहीं है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के वकील द्वारा सजा को कम करने के लिए उठाई गई एकमात्र याचिका थी। एमिकस क्यूरी द्वारा बताई गई निवारणात्मक और कम करने वाली परिस्थितियों पर उच्च न्यायालय ने भी विधिवत ध्यान दिया है। वास्तव में, बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत लगाए गए सात साल के कठोर कारावास की सजा को घटाकर 4 1/2 साल कर दिया। [पैरा 12,13] [762-ई-एफ; 763-डी-ई]

1.2 यह ध्यान में रखना होगा कि अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इस तथ्य पर, आईपीसी की धारा 375 का खंड छठा आकर्षित होगा, जिससे संभोग के लिए उसकी सहमति सारहीन और अप्रासंगिक हो जाएगी। विधानमंडल ने उक्त प्रावधान को ठोस तर्क के साथ पेश किया है और ऐसे प्रावधान के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐसा माना जाता है कि एक नाबालिग तर्कसंगत रूप से सोचने और कोई सहमति देने में असमर्थ है। इस कारण से, चाहे वह नागरिक कानून हो या आपराधिक कानून, नाबालिग की सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है। यहां प्रावधान उस लड़की से संबंधित है जो न केवल नाबालिग है बल्कि 16 वर्ष से कम उम्र की है। एक नाबालिग लड़की को इसके निहितार्थ को समझे बिना ऐसे कृत्य के लिए सहमति देने के लिए आसानी से फुसलाया जा सकता है। इसलिए, इस तरह की सहमति को फायदे और नुकसान के साथ-साथ इच्छित कार्यवाही के परिणामों को समझने के बाद दी गई एक सूचित सहमति नहीं माना जाता है। इसलिए, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई तथाकथित सहमति का लाभ न उठाने का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति पर डाला जाता है। 16 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति होने पर

भी यौन क्रिया में दूसरे साथी को अपराधी माना जाता है जिसने बलात्कार का अपराध किया है। कानून उसके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ता और वह यह दलील नहीं दे सकता कि यह कार्य सहमति से किया गया था। 16 वर्ष से कम उम्र की अभियोक्ता की तथाकथित सहमति को कम करने वाली परिस्थिति नहीं माना जा सकता है। [पैरा 14,15] [763-एफ; 764-बी-एफ]

1.3 एक बार जब चीजों को बताए गए तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है तो मामले का निपटारा किया जाना चाहिए जहां अपीलकर्ता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जिसे जघन्य अपराध माना जाता है। यौन उत्पीड़न के ऐसे कृत्य से घृणा की जानी चाहिए। यदि नाबालिग की सहमति को कम करने वाली परिस्थिति के रूप में माना जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह दृष्टिकोण तब मजबूत हो जाता है जब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के पीछे की मूल भावना को ध्यान में रखा जाता है। [पैरा 16] [764-एफ-एच]

1.4 केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने अब शादी कर ली है, शायद ही कोई कम करने वाली परिस्थिति बन जाती है। इसी तरह, अपीलकर्ता यह दलील नहीं दे सकता कि अभियोक्ता भी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है और इसलिए, अपीलकर्ता के साथ नरम व्यवहार किया जाना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता ने अभियोजक से शादी की है। इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने पहले ही आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा को सात साल के कठोर कारावास से घटाकर 4 1/2 साल कर दिया है। इसलिए, किसी भी मामले में, अपीलकर्ता किसी भी अतिरिक्त दया का हकदार नहीं है। [पैरा 19] [771-ई-एफ]

नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 (4) एससीआर 1012: (2014) 6 एस. सी. सी. 466; सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह और अन्य (2014) 7 एस. सी. सी. 323-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

2014(4) एस सी आर 1012	संदर्भित	पैरा 17
(2014)7 एस सी सी 323	संदर्भित	पैरा 18

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 230/2013

2005 की आपराधिक अपील संख्या 2158 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.04.2011 से

अपीलार्थी के लिए मोहन पांडे (ए. सी.)।

हेमंतिका वाही, जेसल, पूजा सिंह, स्वाति वैभाई, परमानंद कटारा (ए. सी.) प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

न्यायाधिपति ए. के. सिकरी

हालाँकि, इस न्यायालय ने दिनांक 18.09.2012 के आदेश के तहत श्री परमानंद कटारा को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हम इसकी सराहना नहीं करते हैं। हालाँकि, हमारे अनुरोध पर, विद्वान वकील श्री मोहन पांडे, जो अन्य मामले से संबंधित न्यायालय में उपस्थित थे, न्यायालय की सहायता करने के लिए सहमत हुए। उन्हें मामले को देखने और तैयार करने के लिए समय दिया गया था। इसके बाद, मामले की सुनवाई तब की गई जब वह इसके लिए पूरी तरह से तैयार थे।

(2) यह अपील गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2158/2005 में पारित दिनांक 04.04.2011 के फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी है। यहां अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और साथ ही 376 (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और उपरोक्त अपराधों को करने के लिए उन्हें कठोर कारावास की सजा सुनाई गई:

(ए) आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए, विचारण न्यायालय ने उसे तीन साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, इस शर्त के साथ कि जुर्माना का भुगतान न करने पर अपीलकर्ता को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

(बी) आईपीसी की धारा 366 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज दोषसिद्धि के लिए विचारण अदालत द्वारा लगाए गए दंड के तहत पांच साल की कैद और 3,000 रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर दो महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

(सी) आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए, अपीलकर्ता को सात साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, इस शर्त के साथ कि यदि अपीलकर्ता जुर्माना देने में चूक करता है, उसे एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। 45,000/- रुपये की उपरोक्त राशि, यदि अपीलकर्ता द्वारा जुर्माने के रूप में देय हो, पीड़िता को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया। सभी सजाएं एक साथ चलनी थीं।

(3) उपरोक्त सजा के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील में, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि की है। हालाँकि, साथ ही, इसने आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 7 साल के बजाय 4 1/2 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा को कम करके संशोधित किया है। इस एकान्त संशोधन के परिणामस्वरूप अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, साबरकांठा, चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोडासा, गुजरात द्वारा दिनांक 15.09.2005 को पारित शेष निर्णय और सजा की पुष्टि की गई है

अपीलकर्ता को निम्नलिखित परिस्थितियों में आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 के तहत आरोपित किया गया।

दिनांक 01.09.2003 को लगभग 17.15 बजे जब शिकायतकर्ता की पत्नी बाजार से सब्जी खरीदकर लौटी तो उसे अपनी बेटी घर पर नहीं मिली। हंसाबेन से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि अपीलकर्ता उनके घर आया था और उनकी बेटी से बात की थी। इसके बाद अपीलकर्ता बाजार की ओर चला गया और कुछ देर बाद अभियोजन पक्ष भी बाजार की ओर चला गया। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के चाचा की दुकान से पूछताछ की और उसे बताया गया कि अपीलकर्ता और अभियोजक मोडासा बस स्टैंड की ओर गए थे। शिकायत मोडासा बस स्टैंड पर पहुंची, लेकिन अपीलकर्ता या अभियोजक वहां नहीं मिले। अभियोजन पक्ष का यह भी मामला है कि अपीलकर्ता के चाचा के बेटे ने बताया कि उसने अपीलकर्ता और अभियोक्ता-अनीता को कुछ समय पहले मोडासा बस स्टैंड पर देखा था। चूंकि अभियोजक का पता नहीं लगाया जा सका, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा 05.09.2003 को मेघराज पुलिस स्टेशन में उक्त आशय की शिकायत दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत के दो दिन बाद, अपीलकर्ता ने 07.09.2003 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद, आवश्यक पंचनामा तैयार किया गया और अपीलकर्ता और अभियोजन पक्ष के बयान दर्ज किए गए। उन्हें मेडिकल जांच के

लिए भी भेजा गया. अपीलकर्ता और अभियोक्त्री के कपड़े पंचों की उपस्थिति में जब्त कर लिए गए और विश्लेषण के लिए एफएसएल, अहमदाबाद भेजे गए। जांच में अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त सबूत सामने आए। इसके परिणामस्वरूप 30.11.2003 को उनकी औपचारिक गिरफ्तारी हुई। इसके बाद, चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामला सत्र न्यायालय, हिम्मतनगर को सौंप दिया गया था।

(5) आरोप तय होने के बाद मुकदमा आगे बढ़ा. अभियोजन पक्ष ने आरोपों को साबित करने के लिए 11 गवाहों से पूछताछ की। इन गवाहों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	**प्रदर्श**	**गवाहों के नाम**	
1	8	रसिक भाई हीरा भाई दबगर	शिकायतकर्ता/समर्थक
2	10	रसिक भाई हीरा भाई दबगर की बेटी	पीड़ीत /समर्थक
3	15	पूनमचंद लालजी भाई दबगर	गवाह /समर्थक
4	16	राकेश कुमार पूनमचंद	गवाह /समर्थक
5	17	हंसाबेन पूनमचंद	गवाह /समर्थक
6	18	मुलजीभाई दयाशंकर उपाध्याय	जांच अधिकारी जो चार्ज शीट बनाता है
7	25	चन्दनबेन रसिकलाल दबगर	गवाह /समर्थक
8	27	भीकाभाई मन भाई परमार	गवाह /समर्थक
9	28	कानुभाइ जयचंद भाई चौधरी	मुख्यजांच अधिकारी
10	33	डॉ राजकमल श्री अध्याशरण	चिकित्सक अधिकारी
11	39	भारत कुमार बाबर भाई पटेल	नगर पालिका का कर्मचारी

(6) इसके अलावा, निम्नलिखित दस्तावेज़ गवाहों के माध्यम से प्रस्तुत और प्रदर्शित किए गए:

1. प्रदर्श 9 द्वारा मूल शिकायत

2. प्रदर्श 11 द्वारा अपराध स्थल का पंचनामा

3. प्रदर्श 12 द्वारा जब्त पीड़िता एवं आरोपी के कपड़ों का पंचनामा।

4. प्रदर्श 19 द्वारा मुद्दमल प्राप्त करने के लिए एफएसएल की रसीद

5 प्रदर्श 20 द्वारा एफएसएल रिपोर्ट भेजने के संबंध में एफएसएल का अग्रेषण पत्र

6. प्रदर्श 21 द्वारा एफएसएल रिपोर्ट

7. प्रदर्श 22 द्वारा सीरोलॉजिकल विश्लेषण के परिणाम दिखाने वाली रिपोर्ट।

8. प्रदर्श.26 द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र।

9 मुद्दमल प्रेषण नोट प्रदर्श 29 द्वारा।

10. यदी पुलिस द्वारा अभियुक्तों का मेडिकल परीक्षण कराने हेतु प्रदर्श 34.

11. प्रदर्श 35 द्वारा पीड़ित की शारीरिक जांच का मेडिकल प्रमाण पत्र।

12. प्रदर्श 36 द्वारा अभियुक्त की शारीरिक जांच का मेडिकल प्रमाण पत्र।

13. प्रदर्श 40 द्वारा नगर पालिका के जन्म पंजीकरण रजिस्टर का सार।

(7) अभियोजन साक्ष्य के समापन के बाद, अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। अपने बयान में अपीलकर्ता ने कहा कि वह निर्दोष है। उनका बचाव यह था कि वह और पीड़िता एक-दूसरे से प्यार करते थे और पीड़िता की स्वतंत्र सहमति से विवाह बंधन में बंधे थे। उनके बीच 09.03.2003 को उंजा में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, जिसे पंजीकृत भी कराया गया। अपीलकर्ता ने विवाह रजिस्ट्रार, उन्ज़ा द्वारा जारी विवाह के पंजीकरण को दर्शाते हुए प्रदर्श 43 के रूप में विवाह का ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने कहा कि उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था। हालाँकि, उन्होंने बचाव पक्ष के किसी गवाह से पूछताछ नहीं की।

(8) दलीलें सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366 और 376 के तहत आरोप किसी भी उचित संदेह से परे पूरी तरह से साबित हुए हैं। यह मुख्य रूप से इस आधार पर था कि घटना की तारीख यानी 01.09.2003 को पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी और इसलिए, उसके द्वारा कोई सहमति देने का कोई सवाल ही नहीं था और कथित सहमति का कोई मूल्य नहीं था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले का अवलोकन करने से पता चलता है कि उनके अनुसार, निम्नलिखित बिंदु विचार के लिए उठे थे:

1. क्या अभियोजन बिना किसी संदेह के साबित करता है कि इस मामले की पीड़िता घटना के दिन दिनांक 01.09.2003 को नाबालिग थी?

2. क्या अभियोजन बिना किसी संदेह के साबित कर सकता है कि 01.09.2003 को शाम लगभग पौने पांच बजे, आरोपी ने मेघराज से किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना रसिकभाई हीराभाई की नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया था और इस तरह उसने आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध किया है?

3. क्या अभियोजन बिना किसी संदेह के साबित कर सकता है कि उपरोक्त समय और तारीख पर, यह जानते हुए भी कि वह नाबालिग है, आरोपी ने उससे शादी करने और बाहरी वैवाहिक यौन संबंध बनाने के इरादे से उसे बहला-फुसलाकर वैध संरक्षण से अपहरण कर लिया था और उसे ले गया था। किसी अन्य स्थान पर और इस तरह उसने आईपीसी की धारा 366 के तहत दंडनीय अपराध किया है?

4. क्या अभियोजन बिना किसी संदेह के साबित कर सकता है कि उपरोक्त समय और तारीख पर शिकायतकर्ता की पीड़ित नाबालिग बेटी को उसकी कानूनी संरक्षकता से अपहरण कर लिया गया था कि आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे अलग-अलग स्थानों पर ले गया था और एक विवाहित पुरुष होने के बावजूद उसके

साथ बलात्कार किया था। उसकी इच्छा और सहमति और इस तरह उसने आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध किया है?

5. क्या आदेश?

उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक पूछे गए प्रश्नों का निर्णय सकारात्मक था। फैसले में चर्चा से पता चलता है कि यह एक स्वीकृत मामला था कि पीड़ित और आरोपी एक ही समुदाय से थे और वे दोनों एक साथ स्टेशन से बाहर गए थे। यह भी रिकॉर्ड पर स्थापित किया गया था कि उनके बीच अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग समय पर शारीरिक संबंध थे और 09.03.2003 को उन्ज़ा में विवाह भी किया गया था, जिसे विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में विधिवत पंजीकृत किया गया था। हालाँकि, अपीलकर्ता का प्राथमिक बचाव यह था कि अभियोक्ता बालिग थी; वह स्वेच्छा से अपीलकर्ता के साथ गई और अपनी स्वतंत्र इच्छा, इच्छा और सहमति से शारीरिक संबंध के साथ-साथ वैवाहिक गठबंधन में भी प्रवेश किया। इसलिए, विचारण न्यायालय के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस पर मामले का भाग्य निर्भर था, वह पीड़िता की उम्र थी, जिससे यह पता लगाया जा सकता था कि घटना की तारीख पर वह बालिग थी या नहीं।

(10) यह साबित करने के लिए कि प्रासंगिक समय पर पीड़िता 16 वर्ष से कम थी, अभियोजन पक्ष ने उस स्कूल प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि पेश की थी जहाँ उसने पढ़ाई की थी, जिसे 6/4 के रूप में चिह्नित किया गया था। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, आक्षेपित निर्णय में दर्ज विभिन्न कारणों से, राय दी कि यह प्रतिलिपि कानून के अनुसार साबित नहीं हुई थी और इसलिए, अभियोजक की उम्र निर्धारित करने के लिए इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। चूँकि, उसके बाद उच्च न्यायालय में और हमारे समक्ष भी अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर कोई भरोसा नहीं किया गया है,

इसलिए उन कारणों की गहराई में जाना आवश्यक नहीं है, जिन्होंने विचारण न्यायालय को इस विशेष दस्तावेज़ के संबंध में उपरोक्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी किया था।

(11) इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त दस्तावेज़ को खारिज कर दिया गया था, ट्रायल कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर अभियोजन पक्ष के संस्करण को स्वीकार कर लिया कि घटना की तारीख पर अभियोजक की उम्र 16 वर्ष से कम थी। यह निष्कर्ष पीड़िता की मां चंदनबेन के बयान और ढोलका, नगर पालिका, जहां पीड़िता का जन्म हुआ था, द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र (प्रदर्श 26) पर आधारित है। चंदनबेन ने अपने बयान में कहा था कि पीड़िता का जन्म ढोलका, नगर पालिका के एक अस्पताल में हुआ था और प्रदर्श 26 का उत्पादन ढोलका, नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था। इस प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष के आवेदन पर ढोलका, नगर पालिका के एक कर्मचारी को बुलाया गया था। श्री भरत कुमार बाबरभाई पटेल आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित हुए। उन्होंने न केवल इस आशय की गवाही ही दी कि प्रदर्श 26 ढोलका, नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था, बल्कि उक्त साक्ष्य को उक्त नगर पालिका द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर का उत्पादन करके और भी पुष्ट किया गया था, जिसमें क्रम संख्या 1345 पर अभियोजक के जन्म की प्रविष्टि शामिल थी। वर्ष 1988 में पेज नंबर 91 पर। इस दस्तावेज़ की प्रतिलिपि को प्रदर्श 40 के रूप में रिकॉर्ड पर लिया गया था। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हुए, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रदर्श 26 के साथ पढ़े गए प्रदर्श 40 के अनुसार, अभियोजक की जन्म तिथि 28.09.1988 थी और इस आशय की प्रविष्टि 01.10.1988 को रजिस्टर में की गई थी जो स्पष्ट रूप से साबित हुई कि 01.09.1993 को जब अभियोजक को अपीलकर्ता द्वारा ले जाया गया तब उसकी उम्र 16 वर्ष से कम थी (वास्तव में 15 वर्ष से भी कम)। उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह अपहरण का मामला था क्योंकि

उसकी सहमति महत्वहीन थी क्योंकि नाबालिग होने के कारण वह उस उम्र में कोई भी सहमति देने में सक्षम नहीं थी। इसी तरह, चूँकि संभोग को वस्तुतः स्वीकार कर लिया गया है और चिकित्सीय साक्ष्यों द्वारा भी साबित कर दिया गया है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से बलात्कार माना जाएगा। अभियुक्त की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अलावा, संभोग का वास्तविक तथ्य चिकित्सा परीक्षण से साबित हुआ था और डॉ. राज कमल, जिन्होंने पीड़िता के साथ-साथ अभियुक्त की भी जांच की थी, ने इस आशय की गवाही दी थी।

(12) रिकॉर्ड पर मौजूद उपरोक्त सबूतों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा को बरकरार रखा, और यह सही भी है, क्योंकि हमें इससे विचलित होने का कोई कारण नहीं मिला। वास्तव में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील कोई भी तर्क नहीं दे सके जो अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर सके। उपरोक्त सामग्री के सामने, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह केवल सजा कम करने के लिए दबाव डालेंगे। अन्यथा भी, यह रिकॉर्ड की बात है कि अपीलकर्ता के वकील द्वारा पहले भी यही एकमात्र याचिका उठाई गई थीउच्च न्यायालय. इसलिए, विद्वान न्यायमित्र ने हमारा ध्यान आक्षेपित निर्णय के पैरा 12 की ओर आकर्षित किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता की नवविवाहिता हुई थी (जिसका अर्थ है कि अप्रैल, 2011 से ठीक पहले जब उच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया था)। यह भी दलील दी गई कि वह एक गरीब आदमी था और अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। एक और आकस्मिक परिस्थिति जिसे पेश करने की कोशिश की गई वह यह थी कि भले ही घटना के समय पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी, लेकिन पूरा प्रकरण प्रेम प्रसंग का परिणाम था।अपीलकर्ता और अभियोक्ता के बीच और उनके बीच प्रत्येक कार्य सहमति से हुआ था। यह भी बताया गया कि अभियोक्ता भी शादीशुदा थी और उसका एक बच्चा भी था, इसलिए वह खुशी-खुशी अपने वैवाहिक घर में रह रही थी। इन परिस्थितियों के आधार पर अपील की गई कि

अपीलकर्ता के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए उस पर लगाई गई सज़ा को कम करना।

(13) उपरोक्त याचिका को ध्यान में रखते हुए, हमें केवल वर्तमान अपील में सजा के मुद्दे पर विचार करने के लिए कहा गया है। विद्वान एमिकस क्यूरी द्वारा बताई गई कम करने वाली और कम करने वाली परिस्थितियों पर उच्च न्यायालय ने भी विधिवत ध्यान दिया है। वास्तव में, बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 376 के तहत लगाए गए सात साल के कठोर कारावास की सजा को घटाकर 4 1/2 साल कर दिया। हमारा मानना है कि अपीलकर्ता किसी और दया का हकदार नहीं है।

(14) पहली बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि अभियोक्ता की उम्र 16 वर्ष से कम थी। इस तथ्य पर, आईपीसी की धारा 375 का खंड छठा आकर्षित होगा, जिससे संभोग के लिए उसकी सहमति सारहीन और अप्रासंगिक हो जाएगी। इसे इस प्रकार पढ़ें:

> "375. बलात्कार-एक पुरुष को "बलात्कार" करने वाला माना जाता है, जो इसके बाद छोड़े गए मामले को छोड़कर, निम्नलिखित छह विवरणों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में एक महिला के साथ संभोग करता है: -
>
> xx xx xx
>
> छठा - उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह सोलह वर्ष से कम उम्र की हो। स्पष्टीकरण.-बलात्कार के अपराध के लिए आवश्यक संभोग का गठन करने के लिए प्रवेश पर्याप्त है।"

(15) विधानमंडल ने उपरोक्त प्रावधान को ठोस तर्क के साथ पेश किया है और ऐसे प्रावधान के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐसा माना जाता है कि एक नाबालिग तर्कसंगत रूप से सोचने और कोई सहमति देने में असमर्थ है। इस कारण से, चाहे वह नागरिक कानून हो या आपराधिक कानून, नाबालिग की सहमति को वैध सहमति नहीं माना जाता है। यहां प्रावधान एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो न केवल नाबालिग है बल्कि 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़की को इसके निहितार्थ को समझे बिना ऐसे कृत्य के लिए सहमति देने के लिए आसानी से फुसलाया जा सकता है। इसलिए, ऐसी सहमति को इच्छित कार्यवाही के पक्ष और विपक्ष के साथ-साथ परिणामों को समझने के बाद दी गई एक सूचित सहमति नहीं माना जाता है। इसलिए, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की द्वारा दी गई तथाकथित सहमति का लाभ न उठाने का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति पर डाला जाता है। यहां तक कि जब 16 साल से कम उम्र की लड़की की सहमति हो, तो यौन कृत्य में दूसरे साथी को अपराधी माना जाता है जिसने बलात्कार का अपराध किया है। कानून उसके लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ता है और वह यह दलील नहीं दे सकता है कि कार्य सहमति से किया गया था, 16 वर्ष से कम उम्र की अभियोक्ता की तथाकथित सहमति को कम करने वाली परिस्थिति नहीं माना जा सकता है।

(16) एक बार जब हम ऊपर बताए गए तरीके से चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, तो हमें इसे एक ऐसा मामला मानना होगा जहां अपीलकर्ता ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है जिसे जघन्य अपराध माना जाता है। यौन उत्पीड़न के ऐसे कृत्य से घृणा की जानी चाहिए।' यदि नाबालिग की सहमति को कम करने वाली परिस्थिति के रूप में माना जाता है, तो इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हमारा यह दृष्टिकोण तब मजबूत हो जाता है जब हम यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के पीछे की मूल भावना को ध्यान में रखते हैं।

(17) सज़ा देने के पीछे उद्देश्य और औचित्य न केवल प्रतिशोध, अक्षमता, पुनर्वास बल्कि निवारण भी है। सजा के कुछ पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एस सी सी 466 में चर्चा की गई थी। इस समय उक्त चर्चा को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा:

> "14. कानून कुछ कृत्यों और/या आचरण पर रोक लगाता है और उन्हें अपराध मानता है। ऐसे कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति दंडात्मक परिणामों के अधीन है जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अधिकतर, अपराध करने के लिए दी जाने वाली सज़ा या तो कारावास या आर्थिक जुर्माना या दोनों है। कारावास कठोर या सरल प्रकृति का हो सकता है। जो व्यक्ति अपराध करते हैं उन्हें ऐसे दंडात्मक परिणाम क्यों भुगतने पड़ते हैं? ऐसी सज़ा के पीछे कई दर्शन हैं जो इन दंडात्मक परिणामों को उचित ठहराते हैं। दार्शनिक/न्यायशास्त्रीय औचित्य प्रतिशोध, अक्षमता, विशिष्ट निवारण, हो सकता है।सामान्य निवारण, पुनर्वास, या बहाली। उपरोक्त में से कोई भी या उसका संयोजन सज़ा का लक्ष्य हो सकता है।
>
> 15. जबकि विभिन्न देशों में, वैधानिक या अन्यथा, सजा दिशानिर्देश प्रदान किए जाते हैं, जो न्यायाधीशों को विशिष्ट सजा देने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं, भारत में हमारे पास आज तक ऐसी कोई सजा नीति नहीं है। ऐसे दिशानिर्देशों की व्यापकता का उद्देश्य न केवल विभिन्न मामलों में सजा देने में निरंतरता प्राप्त करना हो सकता है, ऐसे दिशानिर्देश आम तौर पर सजा नीति भी निर्धारित करते हैं, अर्थात्, क्या किसी विशेष मामले में सजा देने का उद्देश्य निवारण या प्रतिशोध या पुनर्वास आदि से अधिक है। भारत में ऐसे दिशानिर्देशों के

अभाव में, अदालतें अपराध की विशेष प्रकृति के लिए कुछ निर्दिष्ट दंडात्मक परिणामों के निर्धारण के पीछे के दर्शन के बारे में अपनी धारणा पर चलती हैं। कुछ के लिए निवारण और/या प्रतिशोध अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि अन्य न्यायाधीश सजा के लक्ष्य के रूप में पुनर्वास या बहाली से अधिक प्रभावित हो सकते हैं। कभी-कभी, यह दोनों का संयोजन होगा जो एक विशेष सजा देने में अदालत के दिमाग पर निर्भर करेगा। हालाँकि, यह परिमाण का प्रश्न हो सकता है।

16. सजा के उद्देश्य के पीछे की चर्चा से जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि यदि किसी विशेष अपराध को समाज के खिलाफ अपराध और/या जघन्य अपराध माना जाता है, तो अपराधी को दंडित करने के लिए निवारक सिद्धांत अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जिसे ऐसे मामलों में लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, ऐसे अपराधों के संबंध में जिन्हें समाज के विरुद्ध माना जाता है, अपराधी को दंडित करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार, जब अपराधी और पीड़ित के बीच समझौता हो जाता है, तब भी उनकी इच्छा प्रबल नहीं होगी क्योंकि ऐसे मामलों में मामला सार्वजनिक होता है। समाज की मांग है कि दूसरों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए व्यक्तिगत अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए क्योंकि यह समाज में सबसे बड़ी संख्या में व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी भलाई है। इसी संदर्भ में हमें संहिता की धारा 307 के पीछे की योजना/दर्शन को समझना होगा।

17. हम इस सिद्धांत को और अधिक विस्तार से विस्तारित करना चाहेंगे। व्यवहार में और वास्तविकता में, हम पाते हैं कि दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद और सजा/दंड देते समय अदालत आम तौर पर

उपरोक्त कारकों में से किसी एक या सभी या संयोजन द्वारा शासित होती है। कभी-कभी, यह निवारण सिद्धांत है जो अदालत के दिमाग में प्रबल होता है, विशेष रूप से वे मामले जहां किए गए अपराध जघन्य प्रकृति के हैं या भ्रष्टता दर्शाते हैं, या नैतिकता की कमी है। कभी-कभी यह कानून में "भावना" के तत्व को संतुष्ट करने के लिए होता है

प्रतिशोध/प्रतिशोध मार्गदर्शक कारक बन जाता है, किसी भी मामले में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कानून द्वारा सजा का उद्देश्य न्याय के विचारों से विवश होकर निवारण है। तो फिर, कानून में दया, क्षमा और करुणा की क्या भूमिका है? ये किसी भी तरह से आरामदायक प्रश्न नहीं हैं और यहां तक कि इनके उत्तर भी आरामदायक नहीं हो सकते हैं। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जो बहुत स्पष्ट हों, अर्थात्, समाज और गैर-पक्षों के खिलाफ आपराधिकता के तत्व वाले जघन्य अपराध से जुड़े मामले। ऐसे मामलों में, सजा के उद्देश्य के रूप में निवारण सर्वोपरि हो जाता है और भले ही पीड़ित या उसके रिश्तेदारों ने सद्गुण और सज्जनता दिखाई हो, अपराधी को माफ करने के लिए सहमत हुए हों, उस निजी पक्ष की करुणा बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति को स्वीकार करने के लिए अदालत का रुख नहीं करेगी। ऐसे अपराधों को कम करने के लिए, गलत काम करने वालों को कानून का कड़ा हाथ दिखाना अधिक महत्वपूर्ण है। हत्या, बलात्कार, या अन्य यौन अपराध आदि के मामले स्पष्ट रूप से इस श्रेणी में आएंगे। आख़िरकार, न्याय के लिए दीर्घकालिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, उस श्रेणी में आने वाले अपराध भी हो सकते हैं जहां आपराधिक कानून के "सुधारात्मक" उद्देश्य को

"निरोध" दर्शन के विपरीत अधिक महत्व देना होगा। सज़ा, चाहे जो भी हो, बुराई को बढ़ाने के बजाय उचित और अच्छाई के लिए अनुकूल होनी चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में न्यायालय की राय है कि पक्षों के बीच समझौता हो जाए अच्छे को नजरअंदाज करने की ओर ले जाएगा; उनके बीच बेहतर संबंध; इससे पार्टियों के बीच इस तरह की मुठभेड़ों की आगे की घटना को रोका जा सकेगा निपटान को बेहतर पायदान पर रख सकता है। यह दो परस्पर विरोधी हितों के बीच एक नाजुक संतुलन है जिसे अदालत द्वारा इन सभी मापदंडों की जांच करने के बाद हासिल किया जाना है और फिर यह तय करना है कि किसी विशेष मामले में उसे कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए।"

(18) इसी तरह, इस न्यायालय ने सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह और अन्य, (2014) 7 एसईसी 323 के मामले में यौन अपराधों से जुड़े मामलों में सजा के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

"33. यहां यह कहना प्रतीत होता है कि यद्यपि सजा का प्रश्न विवेक का विषय है, फिर भी उक्त विवेक का उपयोग अदालत द्वारा काल्पनिक और मनमौजी तरीके से नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के लिए बहुत मजबूत कारणों को उक्त विवेक के उदार उपयोग के लिए आधार बनाना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्मिक और अद्वितीय अभिव्यक्ति की ध्वनि, एक तरह से द नेचर ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसेस में बेंजामिन एन. कार्डोज़ो की चेतावनी है - येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 1921 संस्करण, पृष्ठ 114

"न्यायाधीश स्वतंत्र होने पर भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। उसे अपनी खुशी के लिए कुछ नया नहीं करना है। वह सौंदर्य या अच्छाई के अपने आदर्श की खोज में स्वेच्छा से घूमने वाला शूरवीर नहीं है। उसे अपनी प्रेरणा समर्पित सिद्धांतों से लेनी है . उसे अनैच्छिक भावना, अस्पष्ट और अनियंत्रित परोपकार के आगे झुकना नहीं है। उसे परंपरा द्वारा सूचित, सादृश्य द्वारा व्यवस्थित, प्रणाली द्वारा अनुशासित और 'सामाजिक जीवन में व्यवस्था की मौलिक आवश्यकता' के अधीन विवेक का प्रयोग करना है।"

34. इस संबंध में, हम रामजी दयावाला एंड संस (पी.) लिमिटेड बनाम इन्वेस्ट इंपोर्ट, (1981) 1 एससीसी 80 से एक उद्धरण उद्धृत कर सकते हैं:

"20...जब यह कहा जाता है कि कोई मामला अदालत के विवेक के अंतर्गत है, तो इसे तर्क और निष्पक्ष खेल के अनुसार अच्छी तरह से स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि सनक और सनक के अनुसार 'विवेक', आर बनाम विल्क्स, (1770) 4 बूर 2527 में लॉर्ड मैन्सफील्ड ने कहा, 'जब न्याय की अदालत में लागू किया जाता है, तो इसका मतलब कानून द्वारा निर्देशित ध्वनि विवेक है। इसे नियम द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए, हास्य द्वारा नहीं; यह मनमाना, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, और काल्पनिक, लेकिन कानूनी और नियमित"'(देखें क्रेज़ ऑन स्टैच्यूट लॉ, 6 वां संस्करण, पृष्ठ 273)।

35. एयरो ट्रेडर्स प्रा. लिमिटेड बनाम रविंदरकुमार सूरी, (2004) 8 एससीसी 307, न्यायालय ने कहा:

"6....ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार 'न्यायिक विवेक' का अर्थ है न्यायाधीश या अदालत द्वारा परिस्थितियों के तहत जो उचित है उसके आधार पर निर्णय देना और कानून के नियमों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित; एक अदालत काकार्य करने या न करने की शक्ति, जब कोई वादी अधिकार के रूप में कार्य की मांग करने का हकदार नहीं है। 'विवेक' शब्द आवश्यक रूप से एक न्यायिक चरित्र के कार्य को दर्शाता है, और, जैसा कि विवेक के संदर्भ में उपयोग किया जाता हैन्यायिक रूप से प्रयोग करने पर, इसका तात्पर्य एक कठोर नियम की अनुपस्थिति से है, और इसमें निर्णय के वास्तविक अभ्यास और उन तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता होती है जो एक ध्वनि बनाने के लिए आवश्यक हैं,निष्पक्ष और उचित दृढ़ संकल्प, और उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर विवेक ठीक से काम कर सकता है। (27 कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम, पृष्ठ 289 देखें)। जब यह कहा जाता है कि कुछ अधिकारियों के विवेक के भीतर किया जाना है, तो कुछ तर्क और न्याय के नियमों के अनुसार किया जाना है न कि निजी राय के अनुसार; कानून के अनुसार और हास्य के अनुसार नहीं। यह केवल किसी न्यायाधीश को, जो मंत्री या प्रशासनिक अधिकारी से भिन्न हो, उसके समक्ष लाए गए मामलों पर निर्णय देने के लिए क़ानून या नियमों द्वारा प्रदत्त कुछ छूट या स्वतंत्रता देता है।"

इस प्रकार, न्यायाधीशों को लगातार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि विवेक का उपयोग कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और प्राप्त परिस्थितियों में क्या उचित है।

36. विवेक के बारे में चर्चा करने के बाद, अब हम किसी अपराध के लिए सजा देते समय शक्ति के प्रयोग में न्यायालय के कर्तव्य पर ध्यान देंगे। पर्याप्त सजा देना न्यायालय का कर्तव्य है,अपेक्षित सज़ा लगाने का एक उद्देश्य समाज की सुरक्षा और सामूहिक विवेक के प्रति एक वैध प्रतिक्रिया है। लेजर बीम का मार्गदर्शक होने वाला सर्वोपरि सिद्धांत यह है कि सजा आनुपातिक होनी चाहिए। यह सामाजिक चेतना के प्रति कानून का उत्तर है। एक तरह से, यह उस समाज का दायित्व है जिसने बुराई पर अंकुश लगाने के लिए कानून की अदालत में विश्वास जताया है। सजा सुनाते समय यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका और कानून के शासन के प्रति सम्मान की याद दिलाए। इसे तर्कसंगत न्यायिक विवेक को प्रदर्शित करना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत धारणा या नैतिक प्रवृत्ति को। लेकिन, यदि अंततः उचित सजा नहीं दी जाती है, तो सजा का मूल व्याकरण दोषी ठहराया जाता है। कानून इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता; और अंतःकरण की पवित्रता से उसे घृणा होती है। पुरानी कहावत "कानून किसी के अतीत का शिकार कर सकता है" को अशोभनीय तरीके से दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और दया के इंद्रधनुष को, बिना किसी समझ के, शासन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह सच है कि उसका अपना दायरा है, लेकिन, सभी

परिस्थितियों में, उसे पूरे आवास पर कब्ज़ा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में पीड़िता आज भी न्याय की गुहार लगा रही है. हमें नहीं लगता कि जुर्माना राशि में वृद्धि या संहिता के तहत मुआवजा देना कानून में उचित उत्तर होगा। पैसा मरूद्यान नहीं हो सकता. यह सभी मुक्ति के लिए केंद्रीय भूमिका नहीं निभा सकता है। स्पष्ट रूप से अपर्याप्त और अनुचित रूप से उदार सजा में हस्तक्षेप उचित वारंट है, क्योंकि न्यायालय पीड़ित की पीड़ा और पीड़ा और अंततः, समाज की पुकार के प्रति अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाते हुए, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि न्याय का उद्देश्य सबसे अच्छा होगा यदि प्रतिवादी को विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा लगाए गए जुर्माने के अलावा दो साल के कठोर कारावास की सजा दी जाए।"

(19) केवल इसलिए कि अपीलकर्ता ने अब शादी कर ली है, शायद ही कोई कम करने वाली परिस्थिति बन जाती है। इसी तरह, अपीलकर्ता यह दलील नहीं दे सकता कि अभियोक्ता भी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है और इसलिए, अपीलकर्ता के साथ नरम व्यवहार किया जाना चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता ने अभियोजक से शादी की है, इसके बावजूद, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने पहले ही आईपीसी की धारा 376 के तहत सजा को सात साल के कठोर कारावास से घटाकर 41/2 साल कर दिया है। इसलिए, किसी भी मामले में, अपीलकर्ता किसी भी अतिरिक्त दया का हकदार नहीं है। तदनुसार, अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

(20) अपीलकर्ता को वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा कर दिया गया था। तदनुसार, उसे शेष सजा काटने के लिए हिरासत में लिया जाएगा।

निधि जैन अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।